

जिस कदर हम ने आयात किया है उस से ज्यादा हम ने निर्यात किया है।

SHRI BEDABRATA BARUA : As most of the functions of foreign trade have been taken over by STC and MMTC and in view also of the fact that there have been certain political resolutions to that effect, are Government examining the possibility at the present stage ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : The hon. Member has not been categorical as to what Government have to examine. But the fact is that the STC has not taken over the entire trade. We have started exporting wiglets, wigs, falls and also shoes, and are importing synthetic and nylon wares through STC. MMTC is exporting ores.

SHRI D. N. PATODIA : If the press reports are any indication, the STC is likely to take over more and more export trade from time to time. On the other hand, the experience is that over the last few years STC and its associate MMTC had not been able to stand in competition with the free export enterprise. It had been living under the protection of various state patronages and state monopolies. In view of that, may I know whether it is true that, in spite of the bad experience, STC is thinking of taking over more private trade ? And secondly, may I know what was the experience of STC in sealing with the rupee countries where it has been widely reported that India has been great loser by this rupee payment arrangement ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : With regard to the first part of the question, the answer is no. With regard to the second part, our experience with the East European countries has been a very happy one, and we are doing very well.

SHRI D. N. PATODIA : How do you explain the resolution of the Congress working Committee ?

SHRI RANGA : That he ignores.

SHRI VASUDEVAN NAIR : Some time back, soon after the general elections, the Working Committee of the ruling party passed a ten-point programme with great fanfare, and one of the items included in the programme was the nationalisation of import trade. I should like to know from the Minister whether the Government led by that party has taken that decision into

consideration, and whether, if not today at least in the near future, they are thinking of implementing that directive from the Working Committee ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : The point is that we have accepted the principle of a mixed economy, in which both the private sector and the public sector have a place. And this is not the forum to discuss party affairs.

श्री रवि राय : जो आप घोषणा करेंगे उस की पूर्ति नहीं करेंगे।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : I have already stated that wherever Government feels the necessity of taking over any trade which is affecting the economy of the country, its trade and commerce, definitely we will do it.

श्री क० ना० तिवारी : स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में कितने रुपये की लागत है, कितना रुपया इस के ऊपर खर्चा बैठता है और इस की आमदनी कितनी होती है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन पर इस वक्त तक जो सरमाया लगा हुआ है वह 2 करोड़ रुपये का है पेठ अप कैपिटल और इस का जो कारोबार है वह तकरीबन 13 करोड़ रुपये से पिछले साल से बढ़ कर 32 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

WATER METERS FOR BHILAI AND DURGAPUR STEEL PLANT

*542. **SHRI PREM CHAND VERMA :** Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that water meters valued at Rs. 5,18,578/- for Bhilai and Durgapur Steel Works were purchased in 1962 and 1963 ;

(b) whether it is also a fact that these water meters were not put into use till the 31st December, 1966 ;

(c) whether the meters were found defective but the manufacturers refused to take them back ; and

(d) if so, whether any inquiry was instituted to fix responsibility for the loss and, if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) These meters were purchased during the period from January 1962 to September, 1964.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). None of the water meters purchased by Bhilai Steel Plant has been found defective. Information has now been received from Durgapur Steel Plant stating that none of the water meters was found defective. Some meters had been damaged in transit and these were later replaced by the suppliers.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस की बड़ी अहमियत है और वह इसलिए कि जो एक छोटा सा सवाल है वाटर मीटर्स का उस के बारे में जब हम क्वेश्चन देते हैं तो वह यहां आता नहीं है और वह अनस्टांड में भेज दिया जाता है लेकिन मेरा कहना है कि यह वाटर मीटर का छोटा सा मामला एक बड़े मामले का छोटा सा हिस्सा है...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब सवाल पूछें।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह ठीक है कि हिन्दुस्तान स्टील के अफसरों ने भिलाई और दुर्गापुर कारखानों के कर्मचारियों के लिए 5972 वाटर मीटर 1962-63 में खरीदे और 31 मार्च 1966 तक सिर्फ 190 वाटर मीटरों का इस्तेमाल किया जबकि कुल मीटरों की लागतमय इंटरैस्ट के 31 मार्च 1966 को 7,78,078 लाख रुपये थी ?

क्या यह भी दुरुस्त है कि जिस फर्म से यह मीटर खरीदे गये उस ने लगभग तमाम नाकारा मीटर दे दिये और फिर उन्हें लेने से इंकार कर दिया जबकि रकम की अदायगी

बगैर प्रीपर जांच व चैकिंग के कर दी गई और जिस आदमी ने यह सौदा किया था वह आदमी वहां से जा चुका था ?

क्या यह भी दुरुस्त है कि जिन बंगलों और स्टाफ के क्वार्टरों के लिये यह मीटर लिये गये थे वह 1960 में बने थे और 1966 को 31 मार्च तक खाली रहे और सरकारी रिपोर्ट मुताबिक उन बंगलों का किराया 3 लाख 4 हजार रुपये बनता था। 1 लाख 59 हजार रुपये उन बिल्डिंग की देख भाल कलरे के लिये वाच एंड वार्ड स्टाफ जो रखा गया, जो चौकीदार रखे गये उनकी तनख्वाहों पर खर्च किया गया। 1 लाख 95 हजार रुपये जो पैसा खर्च किया गया उस पर इंटरैस्ट का होता है। इस तरह से 6 लाख 58,000 रुपया यह और 7 लाख 78 हजार रुपया वह है। यह मामला 14 लाख 36 हजार 660 रुपये का होता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में क्या कोई इनक्वायरी उन्होंने की है और अगर की है तो उसका क्या नतीजा निकला है ? इस सब की जिम्मेदारी किस पर डाली गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) : इस में दो तीन सवाल उठाये गये हैं। एक तो यह कहा गया है कि खरीदने के बाद बहुत असें तक वे बेकार रखे गए। यह जो खरीदने का काम हुआ वह 1962 से लेकर 1964 तक किया गया। 1960 और 1961 में सप्लाय करने के लिए कहा गया था। यह बात नहीं है कि 1960 और 1961 में ही इनको खरीद लिया गया था। दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है कि खरीदने के बाद उन में कुछ खराबी थी। भिलाई में और दुर्गापुर में जो आए उन में कोई खराबी नहीं थी। ट्रांसपोर्ट में कुछ जो खराबी पैदा हो गई थी इन मीटरों में उनको मैनूफैक्चरिंग ने रिप्लेस भी किया।

यह भी पूछा गया कि उनको फौरन लगाया क्यों नहीं गया। जहां तक लगाने

का सम्बन्ध है जो छोटे लेबरर्स थे जिन के मकानों में इनको लगाया जाना था उनकी तरफ से रिजिस्टेंस हुआ। इसकी वजह यह थी कि मीटर लगाने का मतलब यह होता कि उनको पानी का खर्चा देना पड़ता। बिना खर्चा दिये हुए वे पानी का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मीटर लगाने से उनको यह तकलीफ होती कि उनको पैसा देना पड़ता। इस वास्ते उनकी तरफ से रिजिस्टेंस हुआ। यह कहना कि मैनेजमेंट ने एम्प्लायीज की किसी भी बिल्डिंग में नहीं लगाया है सही नहीं है। 860 वाटर मीटर भिलाई में लगाये गये हैं। दुर्गापुर का जहां तक सम्बन्ध है एक हजार से ज्यादा जिनकी तनख्वाह है उनके मकानात में और जो नाम-एम्प्लायीज हैं जो 225 हैं और जिन की पांच सौ से ज्यादा तनख्वाह है उनके मकानों में मीटर लगाने का काम जारी है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : रिपोर्ट में यह है कि 31 मार्च 1966 तक 190 मीटर केवल लगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकारी रिपोर्ट सही है या जो आडिट रिपोर्ट हमें मिली है वह सही है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि सात लाख रुपये खर्च करके जब मीटर खरीदे गये थे तो क्या इस बात का पता नहीं लगाया गया था कि कर्मचारी इसकी मुखात्फित करेंगे? छः साल तक को खरीद कर आपने रख छोड़ा और बाद में आप कहते हैं कि मुखात्फित हुई है।

डा० चन्ना रेड्डी : आडिट रिपोर्ट का जहां तक ताल्लुक है वह भी सही है क्योंकि वह 1966 तक की है। मार्च, 1967 में लगाने का काम शुरू हुआ। इसलिए जो बयान में दे रहा हूँ वह भी सही है।

क्यों इतनी देर इनको बेकार रखा, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। 1960 और 1961 में उनको भेजने के लिए कहा गया और 1962 से 1964 तक उनको खरीदा गया। जहां तक वर्कर्स की तरफ से रिजिस्टेंस का सवाल है मैनेजमेंट को इसकी कल्पना नह थी कि वे

नहीं चाहेंगे। इसलिए एक साल के करीब जो वक्त खराब हुआ वह वर्कर्स की रिजिस्टेंस की वजह से हुआ।

श्री राम चरण : मैं जानना चाहता हूँ कि इनको क्या डी० जी० एस० डी० की मार्फत खरीदा गया या कंसर्डे अफसरों ने डायरेक्टली इनको खरीदा ?

डा० चन्ना रेड्डी : पब्लिक सेक्टर के लोगों ने डायरेक्ट इनको खरीदा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय, के उत्तर से यह बात साफ नहीं होती कि मीटर इतने दिनों तक क्यों पड़े रहे। आपने कहा है कि 1963 में खरीदे गये लेकिन जैसे जैसे मीटर खरीदे जाते रहे वैसे-वैसे ये लगाये नहीं जाते रहे। कुछ काल तक मीटर बेकार पड़े रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए सरकार ने जांच करके किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयत्न किया है। मजदूरों की ओर से जो विरोध हुआ वह तो बाद में हुआ। लेकिन उससे पहले बेकार पड़े रहने का क्या कारण था ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह ठीक है कि उनको खरीदने के बाद फौरन लगाने का काम नहीं किया गया। किसी को में डिफेंड करना नहीं चाहता हूँ। 1962 और 1964 के बीच खरीदने का काम हुआ। फौरन लगाने का काम क्यों नहीं किया गया इसकी मैं जरूर जांच करूंगा। जहां तक मजदूरों की रुकावट की वजह से न लगने का सम्बन्ध है हमारी यह मान्यता है कि मजदूरों को साथ ले कर, उनको समझा बुझा कर चलना पड़ता है।

श्री मनु चाई पटेल : देरी से जो इनको लगाया उस में तो आप का कसूर हुआ ही। लेकिन जितने खरीदे गये उन में से ज्यादा आप लगा नहीं सके। बहुत से बच गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आवश्यकताओं से ज्यादा के लिए आर्डर देने की क्या जरूरत थी ?

डा० चन्ना रेड्डी : आर्डर तो ज्यादा का नहीं दिया गया और वह इस तरह से कि अगर हम सारे मजदूरों के मकानों में इनको लगायें तो ये कम पड़ेंगे। ज्यादा मीटर खरीदने की कोशिश नहीं की गई है यह बिल्कुल साफ है।

STATE TRADING CORPORATION

*543. **DR. RANEN SEN :** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation is planning to enter into the field of production of exportable goods ; and

(b) if so, the main features of the scheme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes, Sir.

(b) State Trading Corporation is already engaged in the production of wigs, wiglets and falls made of human hair. The STC is also planning to set up a factory for machine made footwear for the export market.

DR. RANEN SEN : The Chairman of the STC reported to the press sometime back that besides these two items mentioned by the minister, STC is contemplating to expand its activity in the production of goods that are exported. If that is so, actually is there any programme to expand the activities of STC in this regard ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : As and when STC feels the necessity of entering into the export market for the benefit of the export trade of the country, definitely it will do so.

DR. RAMEN SEN : That was not the question. It was reported in new papers that the S. T. C. Chairman gave some information to the press that besides the two items which the minister stated, STC is trying to expand its activity for the production of certain goods meant for export.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : There is no such programme under contemplation now.

DR. RANEN SEN : It has been reported earlier in this House that machine tools and certain other goods exported particularly to the East European countries have been sent back to India by those

Governments because they were below the normal standard. The PAC also had recommended that such things should not occur and STC should go into the quality of those goods which are to be exported. In view of this, may I know whether STC thinks it necessary to enter into the production of such commodities which are exported ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : As I have already stated, STC is already engaged in the production of wigs, wiglets and shoes. The target fixed for production of shoes is about 10 million pairs, out of which STC has set up a factory in which 1 million pairs will be produced in a year. 9 million pairs will be produced by the private sector and other agencies. It is with a view to maintain quality and competitiveness of our commodities that STC has taken these steps.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI : In view of the fact that many of the private exporters have been indulging in malpractices in export trade, the idea of taking over the trade and nationalising it was in the air. Will the minister give a categorical answer whether he is prepared to explore the possibilities of nationalisation of the entire export trade in view of past experience, and for that purpose productive effort should also be taken over by the public sector ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : I have already said that there is no proposal to nationalise the entire export trade now.

SHRI N. K. SOMANI : According to the articles of association, the STC is supposed to indulge in trading and not in manufacturing activities. Of late there have been serious complaints from Razno exports of Soviet Russia, which has been rejecting footwear imported from India on a large scale. Therefore, instead of trying to enter into the manufacturing field, why does the STC not provide technical assistance, packing and finance for small-scale manufacturers of Agra, Meerut and other parts of UP instead of going into the manufacturing field, which is completely against the whole concept and definition of trade ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : There is nothing